



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1932 (श०)

(सं० पटना 583) पटना, सोमवार, 16 अगस्त 2010

जल संसाधन (सं०)विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई 2010

सं० अ०सं०-२१/वाद ८-०१/२००६-२७६—भारतीय संविधान के अनुच्छेद-१६२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन विभाग के नहर चाट/भूमि की, कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए बन्दोबस्ती हेतु प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार, बिहार निम्नलिखित नियमावली बनाती है:—

बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ — (1) यह नियमावली बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बन्दोबस्ती की प्रक्रिया —

(क) नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती तीन वर्षों के लिए विभाग द्वारा नियत दर पर इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से गठित समिति द्वारा लॉटरी के आधार पर की जायेगी।

(ख) लॉटरी समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे :—

संबंधित विभागीय कार्यपालक अभियंता — अध्यक्ष

क्षेत्रीय अंचलाधिकारी / प्र०वि०पदा० — सदस्य

संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया — सदस्य

(ग) पूर्व नियत तिथि एवं स्थान पर लॉटरी की कारवाई उपस्थित आवेदनकर्ताओं तथा उक्त समिति के समक्ष की जायेगी।

(घ) संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता हर 3 वर्षों के अंतराल पर ऐसी नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती के लिए सूचना अपने सूचना पट के साथ—साथ संबंधित थाना कार्यालय, संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट

पर तथा उसे उस वर्ष के 15 अप्रैल तक स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में भी प्रकाशित करायेंगे। इस सूचना की एक प्रति स्थानीय विधायक एवं स्थानीय सांसद को भी निर्बंधित डाक से भेजी जाएगी।

3. बंदोबस्ती की पात्रता— बंदोबस्ती के लिए लॉटरी में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति सक्षम/पात्र होंगे, जो नहर/चाट भूमि की बंदोबस्ती के ग्राम के अथवा उसके तीन मील की परिधि के भीतर के पड़ोसी ग्राम के निवासी हों। बंदोबस्ती हेतु लॉटरी में उन्हें निम्न क्रम से प्राथमिकता दी जायेगी—

- (क) भूमिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्य,
- (ख) अन्य कोटि के भूमिहीन सदस्य;
- (ग) वैसे अवकाश प्राप्त सैनिक/शहीद सैनिक की विधवा अथवा उत्तराधिकारी जो भूमिहीन हो।

4. अन्य अध्ययेक्षणः—

- (i) किसी भी सक्षम/पात्र व्यक्ति/परिवार जिन्हें लॉटरी के आधार पर एक बार नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती की गयी हो वे पुनः तुरंत बाद वाली बंदोबस्ती के लॉटरी में भाग लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। हालांकि ऐसा वर्जन पश्चात्वर्ती बंदोबस्ती पर लागू नहीं होगा।
- (ii) बंदोबस्ती हेतु लॉटरी के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व नियत लगान का 10 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में लॉटरी की तिथि के एक दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता/अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। सफल व्यक्तियों को लॉटरी की तिथि के अगले तीन दिनों के भीतर (अग्रधन सहित) कुल लगान की राशि का 50 प्रतिशत तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर ऐसी राशि जमा करने में असफल रहने पर अग्रधन की राशि को भुगतेय लगान के विरुद्ध समायोजित कर दिया जायेगा। असफल व्यक्तियों की अग्रधन राशि लॉटरी के तुरंत बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी।
- (iii) किसी पात्र व्यक्ति को अधिकतम दो एकड़ तक भूमि बंदोबस्ती की जायेगी। किसी विवाद की दशा में संबंधित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के द्वारा बंदोबस्ती नहीं हो सके तो विभाग के स्तर पर इसका विनिश्चय किया जायेगा।
- (iv) यदि भूमि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में हो तथा जहाँ बंदोबस्ती में किसी घटना का पूर्व इतिहास हो, तो संबंधित मुख्य अभियंता, विभाग को उसके बारे में पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगा एवं उस विशिष्ट क्षेत्र में भूमि को बंदोबस्ती की व्यवस्था स्थानीय थाना/अंचलाधिकारी/प्र०वि०प०/अनुमंडलाधिकारी/जिला पदाधिकारी के सहयोग से की जायेगी।

5. नहर चाट/भूमि का प्रभार्य लगान का दर अवधारणः— बंदोबस्ती के लिये कर्णाकित सभी नहर चाट/भूमि की बंदोबस्ती के लिये लगान की दर का अवधारण/पुनरीक्षण विभागीय अधिसूचना संख्या 422, दिनांक 29 जून 2007 द्वारा नियत आधार दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया जायेगा।

6. निरसन— इस नियमावली के आरंभ की तिथि से जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं० 21/वाद-८-०१/२००६-४२६, दिनांक 05 जुलाई 2007 द्वारा निर्गत “बिहार नहर चाट/भूमि बंदोबस्ती नियमावली 2007” निरसित समझी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अजय नायक,  
सरकार के सचिव।

*The 13th July 2010*

No.-21/Wad-8-01/2006-276—In exercise of the powers conferred by Article 162 of the constitution of India, the State Govt. of Bihar makes the following Rules, to provide provision for the settlement of canal chat/land of Water Resource Department for agricultural purposes.

## THE BIHAR CANAL CHAT/LAND SETTLEMENT RULES 2010

1. *Short title, extent and commencement*—(i) These Rules may be called "The Bihar Canal Chat/Land Settlement Rules 2010".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come in to force at once.

2. *Procedure of Settlement* :—(a) The settlement of Canal Chat/Land will be made by a duly constituted committee for a period of three years on a fixed rent, by adopting a method of lottery.

(b) The members of the lottery committee will be as follows:

(i) The concerned Executive Engineer	Chairman
(ii) The Circle officer/The B.D.O. Of the area	Member
(iii) The Mukhiya of the concerned Gram Panchayat	Member

(c) The Lottery for the purpose of Settlement will be opened on the prefixed date and place before the aforesaid committee & the applicants present.

(d) The Executive Engineer of the area on an interval of 3 years, will publish a notice for the settlement of such Canal Chat/Land on his office Notice Board as well as on the Notice Board of the concerned Police Station/Office of the Circle Officer and the Office of the Sub-Divisional Magistrate, while also publishing the same in the local Hindi News-Paper latest by 15th April of that year. A copy of this notice will also be sent to the local M.L.A. & the local M.P. separately through registered posts.

3. *Persons eligible for Settlement* :—Following categories of persons, who are residents of the concerned village or neighbouring villages within a radius of three miles where Canal Chat/Land is to be settled, shall be eligible/competent to participate in the Lottery, starting in order of preference given below:-

- (a) Landless members of Scheduled castes/Scheduled tribes
- (b) Landless members of other categories
- (c) Such retired Soldier/widows or dependents of martyrs who are landless.

4. *Other Requirements* :—(i) Any competent/eligible person/family to whom once the Canal Chat/Land has been settled, will not be entitled to participate in the lottery for the immediate next settlement. However, no such bar would be operative on subsequent settlements.

(ii) For participating in settlement through lottery it shall be essential for the willing persons to deposit an amount of 10% of the pre-fixed rent as earnest money, in the office of the concerned Executive Engineer/Sub-divisional Officer, Water Resource Department, latest by but not later than one day before the date of the lottery. Successful person (s) shall have to deposit 50% of total rent amount so fixed (including the earnest money) within 3 days of the lottery and the rest 50% will be deposited within 15 days from the date of lottery. Failure to deposit such amount in time will lead to forfeiture of the earnest money. The earnest money shall be adjusted against the payable rent at the time of depositing the full rent amount. The earnest money of unsuccessful persons shall be refunded to them soon after the lottery.

(iii) A maximum of up to 2 Acres of land shall be settled to any eligible person. In case of a dispute which can not be settled by the Superintending Engineer/Chief Engineer concerned, it will be decided at the level of the department.

(iv) If the land falls in the extremist infested zone and where there is a prior history of any incident in settling the lands, the concerned Chief Engineer, shall provide full details about it to the Department and arrangement for the settlement of land in the particular area will be made with the co-operation of the local P.S./Circle Officer/B.D.O./Sub-divisional Magistrate/District Magistrate.

5. *Determination of leivable rent of Canal Chat/Land* :—Rate of rent for settlement of all Canal Chat/Land earmarked for settlement will be determined/revised

worked out on the basis of annual increase of 5% over the base rates fixed by the department in the year 2007 vide notification no. 422 dated 29th June 2007.

6. *Repeal*—"Bihar Chat/Land Settlement Rules 2007" issued by Water Resources Department Notification No. 21/Wad-8-01/2006-426, dated 5th July 2007 shall be deemed to be repealed from the date of commencement of these Rules.

By order of the Governor of Bihar,

AJAY NAYAK,

*Principal Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 583-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>